Koraput railway line is one of them. The construction of this rail link within the time-bound programme is very necessary as the entire materials required for the construction of the world's biggest aluminium plant at Damanjodi in Koraput district of Orissa are proposed to be trannsported through this railway route. Another important project, Rs. 20 crore Mancheswar railway workshop, located at Orissa, is under construction. The offices of the Senior Engineers and other administrative offices for the Cuttack-Paradeep line and the Mancheswar railway workshop are located at Calcutta. The location of important offices outside the State causes great discontentment amongst local people, as the people connected with the construction activities have to travel to Calcutta for pursuing various matters. In the process, the construction work of the on-going projects are being delayed and cannot be completed before the target period.

The meaning of a Construction Office in Orissa will enable the details to expedite the completion of the project work. It will provide a great relief to the people connected with the various construction activities. Therefore, the opening of a Construction Office in Orissa deserves the special attention of the Government of India.

In view of this, I demand that a Construction Office of the Ministry of Railway should be opened in Orissa forthwith.

(ii) DELAY IN REPAIR OF THE STEPS OF QUTAB MINAR.

श्री तारिक अनवर (कटिहार): उपाध्यक्ष महोदय, काफी दिनों पूर्व कुतुब दुर्घटना की जांच करने वाले एक सदस्यीय जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि कुतुब की सीढ़ियों की मरम्मत कराई जाए तथा इसके अतिरिक्त भी कई अन्य सुझाव आयोग ने दिये थे। उक्त दुर्घटना में 45 व्यक्तियों की जानें गई थीं ।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा सीढ़ियों की मरम्मत के लिए सम्भवत: 22 हजार रूपए स्वीकृत किए गए । यह भी जानकारी मिली है कि सरकार ने मरम्मत के लिए प्राथमिकता के आधार पर सीमेंट उपलब्ध कराया है किन्तु आज तक मरम्मत का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है । ऐसा समाचार है कि जो सीमेन्ट इस उद्देश्य के लिए है उसके वितरण में अनियमितायें हैं । अनाधिकृत व्यक्ति वहां पर गाइड हैं और किताब बेच रहे हैं ।

इस प्रकार का अनैतिक कार्य करने वालों को दंडित तो किया ही जाना चाहिए, साथ ही इसके सही और पूरे तथ्य सामने आ सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा सारे मामले की जांच कराई जाए । मैं मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे सदन को बतायें कि मरम्मत आदि के कार्य में विलम्ब के क्या कारण रहे और उसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ।

(iii) STEPS TO ARRANGE MORE POWER FOR RAJASTHAN FROM ADJOINING STATES.

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाडमेर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रान्त को इस समय देश के सबसे बड़े विद्युत संकट का सामना करना पड़ रहा है । सन् 1980 में कृषि क्षेत्र में किसानों को दिन में 6 घंटे बिजली, सन् 1981 में घंटे बिजली और सन् 1982 में 4 घंटे बिजली मिलती थी और उस समय भी वह आंख मिचौली करती थी । सन् 1980 में बड़े उद्योगों में 33 प्रतिशत कटौती, सन् 1981 में 44 प्रतिशत कटौती और सन् 1982 से 50 प्रतिशत से भी अधिक कटौती की गई । वर्षा के दिनों में तीन से चार महीने तक लगातार 100-100 प्रतिशत कटौती की गई । लघु उद्योगों में भी 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक कटौती रही ।

औद्योगिक उत्पादन में राज्य में सन् 1980 में 3500 करोड़ रूपये, सन् 81 में 45,00 करोड़ रूपये एवं सन् 82 में 6,000करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और कृषि क्षेत्र में रबी की फसल में 25 से 30 प्रतिशत कम पैदावार हुई और किसानों को करोड़ों रुपये की हानी हुई जिसके

[श्री वृद्धिचन्द्र जैन]

कारण उसी भयंकर गरीबी और कर्ज का सामना करना पड़ रहा है ।

विद्युत उत्पादन की कमी का मुख्य कारण कोटा अणु बिजली घर की दोनों इकाइयों का बार बार खराब होना और साल में अधिकांश महीनों में बन्द रहना है और इस समय भी दोनों इकाइयां बन्द हैं। मध्य प्रदेश सरकार का सतपुड़ा में राजस्थान सरकार को उसका हिसाब नहीं देना है और गांधी सागर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भराव क्षेत्र में कई बांधों का बनाना और कम वर्षा का होना भी है।

राज्य को 180 से 220 लाख यूनेट प्रति दिन बिजली की आवश्यकता है जबकि केन्द्र सरकार द्वारा बदरपुर से बिजली की सहायता देने के उपरान्त भी 90 लाख यूनिट प्रति दिन बिजली मिल रही है।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि वह कृषि एवं उद्योगों के विकास और विस्तार के लिए सिंगरौली से 30 लाख यूनिट प्रति दिन और गुजरात सरकार, जोकि विद्युत की दृष्टि में अच्छी स्थिति में है, 30 लाख यूनेट प्रति दिन लोन के रूप में दिलाया जाय ताकि राजस्थान जोकि चार वर्षों से भयंकर अकाल से प्रभावित है और जिसपर 340 करोड़ रुपये की ओवरड्राफ्ट है और जो बड़े उद्योग संकट से गुजर रहा है, इस संकटमय स्थिति को पार कर सके।

(iv) CENTRAL ASSISTANCE FOR CONSTRUCTION OF PALANA THERMAL POWER PROJECT IN RAJASTHAN.

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो दशक से प्रस्तावित राजस्थान के पलाना ताप बिजली घर के निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं होने से पूरे प्रदेश में चिन्ता व्याप्त है क्योंकि पूरे प्रदेश का किसान, उद्यमी व आम उपभोक्ता स्थायी रूप से भयंकर विद्युत संकट से पीड़ित हो गया है । राजस्थान परमाणु बिजली घर की दोनों यूनिटें स्थायी रूप से बन्द हो जाने से लम्बे समय तक यह भीषण विद्युत संकट बने रहने की सम्भावना है ।

पलाना (बीकानेर) में लिग्नाइट कोयले के विपुल भंडार हैं, उसमें कम से कम 50 वर्ष तक कोयला निकाला जा सकेगा । यहां के कोयले को जर्मन के विशेषज्ञों व जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया ने भी अनुकूल पाया है एवं ऐसी भी जानकारी मिली है कि कोयले की तकनीकी जांच हेतु इसे जर्मनी भेजा गया एवं जर्मनी से प्राप्त रिपोर्ट में भी उसे अनुकूल माना है।

13.00 hrs.

मान्यवर, पलाना थर्मल पावर प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है क्योंकि इसी के माध्यम से ही पूरे प्रदेश के बिजली संकट को काफी हद तक दूर करने में स्थायी रूप से सहायता मिल सकेगी। यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि सैन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी आथोरिटी आफ इन्डिया तथा योजना आयोग ने इस परियोजना को आर्थिक व तकनीकी रूप से लगभग एक वर्ष से भी अधिक समय हुआ स्वीकृति दे दी है। लगभग 107 करोड़ रुपये की इस योजना को भारत पूर्वी जर्मनी संयुक्त आयोग द्वारा पूरा कराने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

राजस्थान सरकार ने पलाना थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु एक चीफ इंजीनियर, अतिरिक्त चीफ इंजीनियर, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर तथा कई अन्य पदों पर नियुक्तियां भी कर दी एवं प्रशासन द्वारा पलाना ग्राम पंचायत में किसी प्रकार के नये निर्माण पर रोक लगा दी गई है । वहां के निवासियों की संम्पत्ति व भूमि का मूल्यांकन कर जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भी प्रेषित कर दी । संपत्ति व भूमि हस्तातरण तथा मुआवजे की शर्तें आदि तय करने के लिए सारा मामला राज्य सरकार के विचाराधीन प्रस्तुत कर दिया गया परन्तु इस स्तर पर पहुंचने के बाद इस परियोजना का कार्य अज्ञात कारणों से या तो आगे रोक दिया गया है अथवा पूरा ही बंद कर दिया गया है। इससे पूरे क्षेत्र में चिंता व्याप्त हो गई है क्योंकि इसी पलाना थर्मल पावर प्रोजेक्ट से ही लोगों को भविष्य के लिए आशाएं हैं वरना वर्तमान हालात में